वहशी की कोई कौम न मजहब

सामयिक

प्रभात कुमार राय

राहुल गांधी ने यहां तक कह डाला कि सभी बम धमाकों को रोका नहीं जा सकता। 99 प्रतिशत धमाकों को तो उनकी सरकार होने से पूर्व ही रोक देती है। राहुल का झूठे आंकड़े गढ़ने में कोई सानी नहीं है। भट्टा पारसौल से लेकर मुंबई धमाकों तक राहुल के बयान झूठे रहे हैं।

आतंकवादी मुंबई पर बर्बर खूनी निशाना लगाने में फिर से कामयाब हो गए। मुंबई पर 1993 से अब तक तकरीबन 14 बार आतंकवादी हमले हो चुके हैं। आतंकवाद के गहन प्रश्न पर हुकूमत को नाकाम करार दिया जा सकता है। आतंकवाद यकीनन सदैव एक अंतर्राष्ट्रीय मसअला रहा, किंतु अमेरिका को आतंकवादी महज एक मर्तबा ही निशाना बना सके। अमेरिका ने अपनी संपूर्ण सैन्य शक्ति को आतंकवाद के तमाम गढ़ों को तहस-नहस करने में झोंक दिया। इसके विपरीत भारत ने अपने सीने पर विगत 23 वर्षों से आतंकवाद के वहशियाना हाथों सबसे अधिक जख्म झेले और कम से कम एक लाख से ज्यादा भारतीय नागरिक खोए। इतनी बरबादी के बावजूद आतंकवाद से आरपार की जंग करने की राजनीतिक इच्छा भारतीय राजसत्ता में कदापि नहीं रही। जब कभी और कहीं आतंकवादी आक्रमण हो जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के साथ समूचा राष्ट्र कुछ दिनों के लिए जाग गया। कुछ वक्त व्यतीत हो जाने के पश्चात और अगला आक्रमण होने तक अजगरी निद्रा में सभी सो जाते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ मुसलसल तौर से जिस तरह की राष्ट्रीय चेतना और सजगता की सदैव दरकार रही, ऐतिहासिक रूप से उसका मुकम्मल अभाव रहा। केंद्रीय गृहमंत्री चिदंबरम ने दो साल पूर्व एंटी टैररिस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना का प्रस्ताव किया, किंतु प्रस्ताव सरकारी फाइलों से आगे नहीं बढ़ सका। आतंकवाद पर नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) के गठन के बावजूद केंद्र और प्रांतीय सरकारों की खुफिया एजेंसियों के मध्य बेहद जरूरी तालमेल का गहन अभाव बना रहा। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मसअला कानून-व्यवस्था का मामूली सवाल नहीं, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार प्रांतीय सरकारों को सौंपकर निश्चिंत हो जाए। राष्ट्र के संपूर्ण खुफिया नेटवर्क को सुनिश्चित तालमेल के साथ कारगर तौर से इस्तेमाल करने का दायित्व केंद्रीय सरकार का है। भारतीय राजसत्ता ने राष्ट्र की खुफिया एजेंसियों को भौतिक और नैतिक रूप से हमेशा बेहद कमजोर बनाए रखा। जहां अमेरिका में एक लाख की आबादी पर औसतन 100 खुफिया एजेंट तैनात रहे और रुस एवं चीन में एक लाख की आबादी पर औसतन 150 खुफिया एजेंट की तैनाती रहती है। इसके विपरीत भारत में एक लाख की आबादी पर औसतन मात्र 10 खुफिया एजेंट ही तैनात रहते हैं। प्रत्येक आतंकवादी आक्रमण के पश्चात प्रायः इसे खुफिया तंत्र की नाकामी करार दिया जाता रहा। लगातार आतंकवादी हमले राष्ट्र की गंभीर अक्षम्य राजनीतिक-सामाजिक विफलता रही। भारत सरकार को अमेरिका और चाइना की तरह ही, विश्वस्तर के बेहद ताकतवर खुफिया नेटवर्क का सृजन करने से आखिर रोक कौन रहा है? अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से मुकाबला करने चली भारत की इंटरनेशनल खुफिया एजेंसी रॉ की कतारों में केवल कुछ हजार एजेंट ही विद्यमान रहे, जबकि पाकिस्तान आईएसआई की कतारों में एक लाख से अधिक एजेंट सदैव मौजूद रहे।

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के जटिल प्रश्न पर वर्तमान सरकार की नीति लचर रही। तकरीबन ऐसी ही नीति एनडीए सरकार की भी थी। अमेरिका के कूटनीतिक दबाव में पाकिस्तानी हुक्मरानों के साथ बेहद नरम रवैया अख्तयार किया और उनके मूल चरित्र को कदाचित संज्ञान में न रखते हुए, उन पर गैर जरूरी भरोसा किया गया। परिणामस्वरुप कूटनीतिक बातचीत के आगाज में पाक सेना ने जेहादियों को आगे कर करगिल की पहाड़ियों पर कब्जा किया। ऐतिहासिक गलतियों से कदाचित कोई सबक न सीखकर वर्तमान सरकार पुनः वही भूल दोहराने पर आमादा है। क्या पाकिस्तान ने अमेरिका के कूटनीतिक दबाव के तहत कभी कश्मीर को बलपूर्वक हड़प करने की शासकीय नीति का परित्याग कर दिया? क्या पाकिस्तान ने कश्मीर में जेहाद का संचालन करने वाले आतंकवादी जेहादी गुटों को प्रश्रय प्रदान करना बंद कर दिया? क्या पाक-अधिकृत कश्मीर में आईएसआई द्वारा बाकायदा शासकीय नीति के तहत आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों को बंद कर दिया? यदि नहीं, तो फिर आखिर किस ठोस धरातल पर वार्ता का कूटनीतिक आयोजन जारी है? भारत को संजीदगी के साथ यदि आतंकवाद से निपटना है तो कूटनीतिक दबावों को दरकिनार करते हुए अपने गहन राष्ट्रीय हितों को दृष्टिगत रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध अपनी नीति का फिर से निर्माण करना होगा। दलगत पूर्वाग्रहों और राजनीतिक मौकापरस्ती का परित्याग करके ही आतंकवाद के प्रश्न पर राष्ट्रीय सहमति का तत्काल सृजन होना चाहिए। भारतीय खुफिया नेटवर्क को विश्व स्तर की कसौटी का निर्मित करने के बेहद कड़े प्रयास किए जाने चाहिए।

प्रत्येक आतंकवादी धमाकों के पश्चात हुकूमत द्वारा रेडअलर्ट जारी कर दिया जाता है और फिर कुछ वक्त व्यतीत हो जाने के बाद हर तरह के अलर्ट से बेपरवाह हो जाना भारतीय राजसत्ता की दुर्भाग्यपूर्ण नियति बन चुकी है। धमाकों के तत्पश्चात राजनेताओं द्वारा मौकापरस्त राजनीतिक बयानबाजी का आगाज कर दिया जाता है। इस बार तो हद दो गई। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने यहां तक कह डाला कि सभी बम धमाकों को रोका नहीं जा सकता और 99 प्रतिशत धमाकों को तो उनकी सरकार होने से पूर्व ही रोक देती है। राहुल गांधी का झूठे आंकड़े गढ़ने में कोई सानी नहीं है। भट्टा पारसौल से लेकर मुंबई धमाकों तक राहुल के झूठे बयानों की एक ही कहानी कायम है। मनमोहन सिंह फरमाते हैं कि आतंकवादी षडयंत्रकारियों के न्याय के कटघरे में यथाशीघ्र लाना चाहिए। आखिर कौन लाएगा पीएम साहब? क्या आपका खैरख्वाह अमेरिका लाएगा? 1993 के मुंबई धमाकों के मुलजिमों का मुकदमा 18 वर्ष बाद सुप्रीमकोर्ट में पेंडिंग है। अनेक खूंखार आतंकवादी फांसी की उम्मीद में जेल में बूढ़े हो रहे हैं। अब वक्त है कि अनर्गल बयानबाजी से ऊपर उठ कर हुकूमत आतंकवाद के विरुद्ध कुछ कर दिखाए। अन्यथा इतिहास किसी को कदाचित माफ नहीं किया करता। जरूरी यह भी है कि आतंकवाद को किसी खास मजहब से जोड़कर देखने की प्रवृति का खात्मा होना चाहिए। इसके लिए साहिर लुधियानवी की उल्लेखनीय कारगर पंक्तियों का स्मरण करें-

किसी वहशी की कोई कौम न, कोई मजहब न, कोई जात
उसके लिए इन अल्फाज का जबान पर लाना हराम है

(लेखक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं)

Reproduced by www.hobbyshobby.com with author's permission